पीएम मोदी का ऐतिहासिक ऐलान अब इंडोनेशिया में खुलेगा IIM बेंगलुरु

विषय सूची (Table of Contents):

>> 1. पीएम मोदी का ऐतिहासिक ऐलान इंडोनेशिया में खुलेगा IIM बेंगलुरु का पहला विदेशी...
>> वैश्विक मंच पर भारतीय प्रबंधन की पहचान...
>> द्विपक्षीय संबंधों में मील का पत्थर...
>> 2. आसियान क्षेत्र के युवाओं के लिए नए अवसर सिंगापुरी SEZ में बनेगा अंतरराष्ट्रीय...
>> आसियान (ASEAN) देशों को सीधा फायदा...
>> भविष्य के ग्लोबल लीडर्स होंगे तैयार...
>> 3. भारत और इंडोनेशिया के बीच 14 अहम समझौते खनिज, इस्पात और समुद्री सुरक्षा पर फ...
>> महत्वपूर्ण खनिज और इस्पात आपूर्ति शृंखला...
>> सहयोग के प्रमुख 14 क्षेत्र...
>> 4. डिजिटल और तकनीकी विकास पर जोर एआई (AI) और स्टार्टअप इकोसिस्टम को मिलेगी रफ्तार...
>> आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर...
>> स्टार्टअप इकोसिस्टम का विस्तार...
>> 5. भारत-इंडोनेशिया संबंधों का सुनहरा अध्याय 21वी सदी पर दिखेगा इसका स्थायी प...
>> साझा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत...
>> वैश्विक संतुलन में भूमिका...
>> 6. रणनीतिक साझेदारी को मिलेगी मजबूती व्यापार और रक्षा सहयोग के नए आयाम...
>> व्यापार और आर्थिक सुरक्षा...
>> सुरक्षा और रक्षा सहयोग...
>> 7. मेरे भीतर भारतीय अंश है इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो का खास बय...
>> राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो का बयान...
>> निष्कर्ष...
>> अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)...

IIM Bangalore First International Campus:भारत और इंडोनेशिया के बीच वैश्विक और शैक्षिक संबंधों के इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी तीन देशों की आधिकारिक यात्रा के पहले चरण में सोमवार को जकार्ता पहुंचे। इस ऐतिहासिक दौरे के दौरान भारत और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों को एक नई ऊंचाई मिली है, जब पीएम मोदी ने घोषणा की कि भारत का प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थान, आईआईएम बेंगलुरु (IIM Bangalore), अपना पहला विदेशी परिसर इंडोनेशिया में स्थापित करने जा रहा है।

यह फैसला न केवल दोनों देशों के बीच उच्च शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देगा, बल्कि पूरे आसियान (ASEAN) क्षेत्र के युवाओं के लिए वैश्विक स्तर की प्रबंधन शिक्षा के द्वार भी खोलेगा। साल 2026 की इस सबसे बड़ी शैक्षणिक घोषणा ने

वैश्विक स्तर पर भारतीय शिक्षा व्यवस्था की धाक को और मजबूत कर दिया है। आइए इस महत्वपूर्ण समझौते और पीएम मोदी के इंडोनेशिया दौरे से जुड़ी हर बड़ीlatest updateको विस्तार से समझते हैं।

1. पीएम मोदी का ऐतिहासिक ऐलान: इंडोनेशिया में खुलेगा IIM बेंं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 से 8 जुलाई 2026 तक इंडोनेशिया की आधिकारिक यात्रा पर हैं। जकार्ता में आयोजित एक संयुक्त प्रेस बयान के दौरान पीएम मोदी और इंडोनेशिया के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो ने इस ऐतिहासिक समझौते की आधिकारिक घोषणा की। यह मील का पत्थर दोनों देशों के बीच गहरे होते जा रहे सांस्कृतिक और रणनीतिक रिश्तों का सीधा परिणाम है।

वैश्विक मंच पर भारतीय प्रबंधन की पहचान

भारतीय प्रबंध संस्थान (IIM) बेंगलुरु को दुनिया के सबसे बेहतरीन बिजनेस स्कूलों में गिना जाता है। इंडोनेशिया में इसका पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर खुलना इस बात का प्रमाण है कि भारतीय शिक्षा पद्धति और प्रबंधन कौशल की मांग अब वैश्विक स्तर पर बढ़ रही है। इस परिसर के जरिए छात्रों को विश्व स्तरीय पाठ्यक्रम और शोध के अवसर मिलेंगे।

द्विपक्षीय संबंधों में मील का पत्थर

आईआईएम बेंगलुरु की ओर से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि यह द्विपक्षीय समझौता भारत-इंडोनेशिया सहयोग की दिशा में एक बेहद अहम पड़ाव है। संस्थान के अनुसार, यह अंतरराष्ट्रीय परिसर दोनों देशों के बीच केवल शैक्षिक आदान-प्रदान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह इस पूरे क्षेत्र के लिए भविष्य की नेतृत्व प्रतिभा (Leadership Talent) को विकसित करने की हमारी साझा प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। इस प्रकार युवाओं कीप्रतिभा को मिलेगा पंखऔर वे वैश्विक मंच पर चमक सकेंगे।

2. आसियान क्षेत्र के युवाओं के लिए नए अवसर: सिंघासारी SEZ मे

इस ऐतिहासिक अंतरराष्ट्रीय परिसर को इंडोनेशिया के प्रसिद्ध सिंघासारी विशेष आर्थिक क्षेत्र (Singhasari Special Economic Zone - SEZ) में स्थापित किए जाने की उम्मीद है। यह क्षेत्र अपनी आधुनिक बुनियादी सुविधाओं और तकनीकी विकास के लिए जाना जाता है, जिससे यह संस्थान के लिए एक आदर्श स्थान साबित होगा।

आसियान (ASEAN) देशों को सीधा फायदा

इस परिसर का लाभ केवल इंडोनेशिया के छात्रों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे आसियान (Association of Southeast Asian Nations) क्षेत्र के शिक्षार्थियों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। वर्तमान में आसियान देशों के युवाओं को उच्च स्तरीय प्रबंधन शिक्षा के लिए पश्चिमी देशों का रुख करना पड़ता था, लेकिन अब उन्हें अपने ही क्षेत्र में भारतीय मानकों वाली किफायती और विश्व स्तरीय शिक्षा मिल सकेगी।

भविष्य के ग्लोबल लीडर्स होंगे तैयार

>> आधुनिक पाठ्यक्रम:संघिासारी परिसर में उद्योग जगत की मांग के अनुसार डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और ग्लोबल बिजनेस से जुड़े कोर्स उपलब्ध होंगे।

>> रोजगार के नए अवसर:दक्षिण-पूर्व एशिया में काम कर रही बहुराष्ट्रीय कंपनियों को स्थानीय स्तर पर ही कुशल प्रबंधकीय प्रतिभा मिल सकेगी।

>> सांस्कृतिक जुड़ाव:भारत और आसियान देशों के छात्रों के एक साथ पढ़ने से दोनों क्षेत्रों के बीच सांस्कृतिक और व्यावसायिक संबंध और गहरे होंगे।

3. भारत और इंडोनेशिया के बीच 14 अहम समझौते: खनिज, इस्पात और

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति प्रिबावो सुबियांतो के बीच हुई व्यापक द्विपक्षीय वार्ता के बाद दोनों देशों ने अलग-अलग क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए कुल 14 महत्वपूर्ण समझौतों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2018 में तय की गई भारत-इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देना है।

महत्वपूर्ण खनिज और इस्पात आपूर्ति शृंखला

औद्योगिक और आर्थिक प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए दोनों देशों ने खनिज और इस्पात आपूर्ति शृंखला की अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी में सहयोग करने के लिए एक विशेष समझौते पर मुहर लगाई है। इससे दोनों देशों में कच्चे माल की उपलब्धता आसान होगी और विनिर्माण क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। दोनों देशों के विधिक नियमों को समझने के लिए आपइंडिया कोड पोर्टलकी मदद ले सकते हैं जहां कानूनी डिजिटल दस्तावेज उपलब्ध हैं।

सहयोग के प्रमुख 14 क्षेत्र

इन हस्ताक्षरित समझौतों के तहत कई महत्वपूर्ण डोमेन को शामिल किया गया है, जिनकी विस्तृत सूची (list) इस प्रकार है:

>> समुद्री सुरक्षा (Maritime Security):हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा और नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना।

>> दवाएं और स्वास्थ्य (Pharmaceuticals):सस्ती और गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाओं की आपूर्ति बढ़ाना।

>> अंतरिक्ष और अनुसंधान (Space Research):उपग्रह प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष विज्ञान में साझा विकास।

>> खाद्य सुरक्षा (Food Security):कृषि तकनीकों का आदान-प्रदान और खाद्यान्न संकट से निपटने की साझा रणनीति।

4. डिजिटल और तकनीकी विकास पर जोर: एआई (AI) और स्टार्टअप इकोस

21वी सदी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, पीएम मोदी और इंडोनेशियाई राष्ट्रपति ने भविष्य की तकनीकों पर सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित किया है। द्विपक्षीय वार्ता के बाद दोनों नेताओं ने युवाओं के बीच तकनीकी सहयोग को मजबूत करने के लिए विशेष डिजिटल पैकेजों की घोषणा की।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर

भारत अपने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) जैसे यूपीआई (UPI) और डिजिलॉकर के लिए दुनिया भर में मशहूर है। अब भारत इस तकनीक को इंडोनेशिया के साथ साझा करेगा। इसके साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और दूरसंचार (Telecommunications) के क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान और नवाचार (Innovation) को बढ़ावा देने पर भी सहमति बनी है।

स्टार्टअप इकोसिस्टम का विस्तार

भारत और इंडोनेशिया दोनों ही देशों में दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ स्टार्टअप परिवेश मौजूद है। इस नए समझौते के तहत दोनों देशों के टेक-स्टार्टअप्स को एक-दूसरे के बाजारों में सीधे प्रवेश करने, निवेश हासिल करने और अपनी तकनीक को साझा करने के लिए एक मजबूत मंच मिलेगा। इससे दोनों देशों के युवा उद्यमियों को आगे बढ़ने का बेहतरीन मौका मिलेगा।

5. भारत-इंडोनेशिया संबंधों का सुनहरा अध्याय : 21वी सदी पर

संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन नई पहलों और समझौतों को भारत-इंडोनेशिया संबंधों का एक सुनहरा अध्याय करार दिया। उन्होंने विश्वास जताया कि जकार्ता में लिए गए ये रणनीतिक फैसले केवल तात्कालिक लाभ के लिए नही हैं, बल्कि इनका 21वी सदी के वैश्विक परिदृश्य पर एक स्थायी और गहरा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

साझा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत

भारत और इंडोनेशिया का रिश्ता हजारों साल पुराना है। रामायण, महाभारत और साझा चोल साम्राज्य के इतिहास से लेकर आज के आधुनिक व्यापारिक रिश्तों तक, दोनों देशों के बीच एक स्वाभाविक जुड़ाव रहा है। पीएम मोदी की इस यात्रा ने उस प्राचीन ऐतिहासिक सांस्कृतिक कड़ी को आधुनिक आर्थिक और तकनीकी साझेदारी में बदल दिया है।

वैश्विक संतुलन में भूमिका

ग्लोबल साउथ (Global South) के दो बड़े और प्रभावशाली देशों के रूप में, भारत और इंडोनेशिया का एक साथ आना वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था में एक नया संतुलन पैदा करता है। दोनों देश मिलकर विकासशील राष्ट्रों की आवाज को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर और मजबूती से उठा सकेंगे।

6. रणनीतिक साझेदारी को मिलेगी मजबूती: व्यापार और रक्षा सहयोग

पीएम मोदी के इस दौरे का एक और मुख्य एजेंडा दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और रक्षा सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों और हिंद-प्रशांत (Indo-Pacific) क्षेत्र की भू-राजनीति को देखते हुए यह सहयोग और भी महत्वपूर्ण हो जाता है।

व्यापार और आर्थिक सुरक्षा

दोनों पक्षों ने व्यापारिक बाधाओं को दूर करने और द्विपक्षीय व्यापार के लक्ष्यों को समय से पहले हासिल करने की प्रतिबद्धता जताई है। खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर एक-दूसरे की मदद करने की रणनीति तैयार की गई है, जिससे वैश्विक संकट के समय भी दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं सुरक्षित रह सकें।

सुरक्षा और रक्षा सहयोग

समुद्री सीमाओं को साझा करने के कारण दोनों देशों के लिए समुद्री सुरक्षा सर्वोपरि है। दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास बढ़ाने, समुद्री डकैती को रोकने और रणनीतिक समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नए सुरक्षा प्रोटोकॉल पर सहमति बनी है।

7. मेरे भीतर भारतीय अंश है : इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्रबावो

इस आधिकारिक यात्रा का सबसे भावुक और चर्चा में रहने वाला पल वह था जब जकार्ता में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने दोनों देशों के आत्मीय संबंधों का जिक्र किया। पीएम मोदी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो की तारीफ करते हुए उन्हें भारत का सच्चा और असली दोस्त बताया।

राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो का बयान

पीएम मोदी की इस बात का गर्मजोशी से जवाब देते हुए राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो ने एक बेहद आत्मीय और ऐतिहासिक बयान दिया। उन्होंने कहा, मेरे भीतर भारतीय अंश (भारतीय डीएनए) हैं। उनके इस बयान ने जकार्ता में मौजूद भारतीय प्रवासियों का दिल जीत लिया और सोशल मीडिया पर यह बयान तेजी से वायरल हो रहा है।

यह बयान दोनों देशों के बीच केवल कूटनीतिक रिश्तों को ही नहीं, बल्कि उस गहरे पारिवारिक और सांस्कृतिक जुड़ाव को भी प्रदर्शित करता है, जो सदियों से भारत और इंडोनेशिया के लोगों के दिलों में धड़कता आया है।

निष्कर्ष

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 6-8 जुलाई 2026 की इंडोनेशिया यात्रा पूरी तरह से सफल और ऐतिहासिक साबित हुई है। इंडोनेशिया में आईआईएम बेंगलुरु (IIM-B) का पहला विदेशी परिसर खोलने की घोषणा ने जहां शिक्षा क्षेत्र में एक नई क्रांति की शुरुआत की है, वहीं 14 अलग-अलग समझौतों ने रक्षा, एआई, और खनिज आपूर्ति शृंखला जैसे क्षेत्रों में भारत की स्थिति को मजबूत किया है। राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो का भारत के प्रति गहरा प्रेम यह साफ संकेत देता है कि आने वाले समय में दोनों देशों की यह रणनीतिक और व्यापक साझेदारी 21वी सदी के एशिया को एक नई दिशा देने का काम करेगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

उत्तर: भारतीय प्रबंध संस्थान (IIM) बेंगलुरु का पहला विदेशी और अंतरराष्ट्रीय परिसर इंडोनेशिया में स्थापित किया जा रहा है।

उत्तर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 जुलाई 2026 को इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो के साथ एक संयुक्त प्रेस बयान के दौरान यह ऐलान किया।

उत्तर: यह अंतरराष्ट्रीय परिसर आईआईएम बेंगलुरु और सिंघासारी विशेष आर्थिक क्षेत्र (Singhasari SEZ) के बीच हुए समझौते के आधार पर उसी एसईजेड में बनने की उम्मीद है।

उत्तर: इस प्रस्तावित परिसर से इंडोनेशिया के साथ-साथ पूरे आसियान (ASEAN) क्षेत्र के शिक्षार्थियों और युवाओं को विश्व स्तरीय प्रबंधन शिक्षा का सीधा लाभ मिलेगा।

उत्तर: इस दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच कुल 14 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाएंगे।

उत्तर: दोनों देशों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), दूरसंचार (Telecom), डिजिटल सार्वजनिक ढांचा (DPI) और स्टार्टअप इकोसिस्टम जैसे क्षेत्रों में युवाओं के बीच तकनीकी सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है।

उत्तर: इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य 2018 की भारत-इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत द्विपक्षीय व्यापार, सुरक्षा, और समुद्री सहयोग को और अधिक मजबूत करना है।

उत्तर: इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो ने दोनों देशों के गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करते हुए कहा कि मेरे भीतर भारतीय अंश (भारतीय डीएनए) है।

उत्तर: इस ऐतिहासिक समझौते से जुड़ी विस्तृत आधिकारिक सूची (list), प्रेस विज्ञप्ति और समझौता ज्ञापनों के दस्तावेज विदेश मंत्रालय (MEA) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक किए जा सकते हैं, जहाँ सभी नवीनतम अपडेट (latest update) उपलब्ध रहते हैं।